

TRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUD-DIN AHMED): (a) and (b) Yes, Sir. Government is keen to promote exports of agricultural items like rice, spices, fresh fruits, vegetables, processed foods, floriculture items, cashew, sugar, etc. In the case of items of mass consumption the Policy of the Government is to allow exports only when there are sufficient surpluses. For the year 1993-94 a target of US \$ 2255 million has been fixed for agricultural exports. |

(c) The export price realisation -will depend upon factors like prevailing price, quality of goods supplied, delivery schedule, demand and supply position and a number of other factors and is subject to wide fluctuations.

Indicative current international price of some of the items are given below:—

Rice ~ US \$ 225 — 230 PMT  
White sugar — US \$ 274 PMT  
Raw sugar — US \$ 230 PMT

(d) the farmers can also export their produce directly if they so wish. No licence is required for export except in case of a few specified items.

(e) Government does not propose to import any of the items mentioned above except where such imports are considered absolutely unavoidable in view of serious shortages in the domestic market or where such imports are considered helpful for augmenting exports.

#### अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री-खाद्य-पदार्थ बाजार में भारत का हिस्सा

548. श्री अजीत जोगी :

श्रीधर हरि सिंह :

कृषि प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या यह सच है कि क़ायत आठ वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री-खाद्य-पदार्थ बाजार में भारत का हिस्सा 12 प्रतिशत से 16 प्रतिशत के बीच रहा है, जबकि इस अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दुगुना हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार होने के बावजूद भी समुद्री-खाद्य-पदार्थ उद्योग द्वारा अपनी क्षमता का संपूर्ण दोहन कर पाने में असफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और खाद्यजनित वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) 1980 से 1989 तक के वर्षों के दौरान विश्वव्यापी समुद्री खाद्य व्यापार में भारत का योगदान इस प्रकार रहा।

वर्ष	विश्व व्यापार (बिलियन अमरीकी डॉलर)	भारत के योगदान का प्रतिशत
1980	16.03	1.68
1981	16.64	1.91
1982	16.91	2.11
1983	17.11	2.06
1984	17.19	1.94
1985	18.62	1.61
1986	24.26	1.49
1987	30.54	1.24
1988	35.32	1.22
1989	35.90	1.09

विश्वव्यापी समुद्र खाद्य व्यापार के आंकड़े केवल वर्ष 1989 तक के लिए ही उपलब्ध हैं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य व्यापार में हमारा योगदान बढ़ाने में कुछ मुख्य-मुख्य क़ायाएँ नीचे बताई गई हैं:—

(क) गहरे समुद्र वाले ऐसे जलपथों की अपर्याप्त संख्या जो मछली पकड़ने की लम्बी यात्रा करने और 50 मीटर से अधिक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में सक्षम हों;

(ख) श्रिम्प से भिन्न जिन संसाधनों का उपयोग कम हुआ है अथवा नहीं हुआ है उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए विधिविकृत मछली पकड़ने का कार्य करने हेतु तकनीकज्ञों का अभाव;

(ग) मछली पालन क्षेत्र का धीमा विकास जोकि 65,000 हेक्टेयर तक सीमित है जबकि मछली पालन के लिए उपयुक्त क्षेत्र लगभग 1.4 मिलियन हेक्टेयर है;

(घ) मौजूदा मछली पालन फार्मों की कम उत्पादकता क्योंकि वैज्ञानिक पालन का प्रचलन अधिक नहीं है;

(ङ) वैज्ञानिक पालन के विकास के लिए बीजों और चारे की कमी;

(च) मछली पालन का विकास केवल श्रिम्प पालन तक ही सीमित होना और निर्यातयोग्य दूसरे समुद्री उत्पादों का पालन आरंभ नहीं किया जाना;

(छ) अधिकांश प्रोसेसिंग एक्को द्वारा केवल बलक

प्रशिक्षित मजदूरों का उत्पादन कम मूल्य वर्धन के साथ किया जाना;

(ब) प्राउन्ड मस्लियों की प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग एककों का सुसज्जित नहीं होना;

(घ) अधिकांश निर्यात का उपभोक्ता पैकों के बजाए संस्थागत पैकों में होना;

(ङ) संसाधनों के अनुकूलतम शोषण हेतु बुनियादी सुविधाओं का पूरी तरह से विकास नहीं होना;

(ग) समुद्री उत्पाद क्षेत्र से निर्यात आय बढ़ाने के लिए अपनाई जा रही कार्य नीतियां इस प्रकार हैं :—

(1) निर्यात उत्पादन बढ़ाने के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य और विविधीकृत फिशिंग का विकास;

(2) पालन मत्स्य की दारा उत्पादन बढ़ाना;

(3) नई तकनीकाओं और मूल्यवर्धन आरंभ करना;

(4) प्रोसेसिंग सुविधाओं का आधुनिकीकरण, क्वालिटी उन्नयन और अप्रशिष्ट मूल में कमी लाना; और;

(5) उत्साही बाजार संवर्धन उपाय ।

549. [Transferred to 6th August, 1993].

#### **BAN on Import of Products Involving Chilli Labour**

550. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that USA and some European countries have decided to ban the import of products made by children in countries like India which is likely to adversely affect our exports;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what remedial action Government propose to take in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (c) Private members bills have been introduced in the US Congress to prohibit the importation of goods produced abroad by child labour. The legislation is general in nature and is not aimed at any particular country or product. It has not yet been passed by the Congress. A campaign

against the use of bonded child labour in the production of carpets has been initiated by certain private organisations in Germany.

Government have been improving the enforcement of the relevant laws. Efforts have also been made to persuade the carpet industry itself to cooperate in the elimination of child labour. A programme for rehabilitation of displaced child workers has also been undertaken Steps have also been taken to publicise these measures and to bring out the employment of children in its proper perspective.

#### **India's Export Rate during 1992-93**

551. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE:

SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India's exports during 1992-93 have recorded a growth rate of only 2.81 per cent against an envisaged growth rate of 13.6 per cent during 1992-93;

(b) if so, what are the reasons of such a poor performance; and

(c) what is the target of growth rate for the year 1993-94 and what measures have been adopted to achieve the target ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) As per provisional figures aggregate exports during 92-93 amounted to US \$ 18420 million as compared to US \$ 17779 million in 91-92 registering an increase of 3.61%,

(b) Among the reasons of slow growth in export mention may be made of the sharp decline in exports of to CIS and East European countries and recession in industrially advanced countries.

(c) Export target for 1993-94 has been set at US \$ 22138 million. This reflects a rate of growth of 20% over the provisional aggregate exports of US \$ 18420 million during 1992-93. In the improved environment of the new EXIM Policy, supplemented by reduction in custom tariffs particularly for export related imports, introduction of full convertibility of Rupee on Trade Account, besides emerging trend in export growth in recent months, the export